जलवायु परिवर्तन – एक उभरती चुनौती*

श्री एम. राजेश्वर राव

नमस्कार,

सबसे पहले इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे यह संबोधन देने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करने हेतु मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। हम, केंद्रीय बैंकर के रूप में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करते हैं और इस तरह की विविध सभाएँ हमें उन मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती हैं जो न केवल वित्तीय दुनिया में फैले हैं बल्कि कार्य की व्यापक योजना पर भी प्रभाव डालते हैं। उद्देश्य उन मुद्दों को चिह्नित करना है जिनका पारंपरिक वित्तीय जोखिमों से परे व्यापक प्रभाव है। इसलिए, मैं भारतीय वित्तीय दृष्टिकोण पर विस्तार से चर्चा करूँगा ही, साथ में मैं इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे और अधिक टिकाऊ विकास की ओर संक्रमण प्रक्रिया में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका पर भी चर्चा करना चाहूँगा।

भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का परिदृश्य

वैश्विक वित्तीय प्रणाली विभिन्न कार्यक्षेत्रों से अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रही है, जिसमें बड़े सार्वजनिक ऋण, तनावपूर्ण आस्ति मूल्यांकन, आर्थिक और वित्तीय विखंडन, भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ते साइबर खतरों से उत्पन्न जोखिम शामिल हैं। इन वैश्विक चुनौतियों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था एक अलग पहचान रखती है, जो मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी स्थिति को दर्शाती है। आर्थिक गतिविधि लगातार बढ़ रही है जिसे वित्तीय प्रणाली का समर्थन प्राप्त है और पहले की तुलना में अधिक मजबूत दिखाई देती है।

यदि हम 2021-22 में कोविड के बाद आए उछाल को छोड़ दें, तो 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि 2016-17 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो उम्मीदों से अधिक है। 2020 से पहले[1] संवृद्धि स्तर का औसत 7 प्रतिशत था जो बाद की अवधि के दौरान औसतन 8 प्रतिशत या उससे अधिक रहा। यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू कारकों द्वारा संचालित थी। वर्तमान में मुद्रास्फीति 2024-25 में औसतन 4.5 प्रतिशत और 2025-26[2] में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसलिए, ये समष्टि आर्थिक स्थितियाँ भविष्य में टिकाऊ संवृद्धि की नींव रख सकती हैं, खपत की स्थिति में सुधार कर सकती हैं, निवेश के माहौल को मजबूत कर सकती हैं और बाहरी प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती हैं।

केवल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र ने पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता जैसे प्रमुख मापदंडों में महत्वपूर्ण सुधार प्रदर्शित किया है जिसे मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी स्थितियों और व्यावसायिक भरोसे का सहारा मिला। ऋण विस्तार में निरंतर वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्य हिस्सेदारी व्यक्तिगत ऋण और सेवा क्षेत्र को दिए गए ऋण की है। मार्च 2024 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने 16.8 प्रतिशत की पूंजी और जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) और 13.9 प्रतिशत का सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) अनुपात दर्ज किया। इसके अलावा, एससीबी ने अपने सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में 2.8 प्रतिशत और निवल गैर-निष्पादित आस्ति (एनएनपीए) अनुपात में 0.6 प्रतिशत पर कई वर्षों का निचला स्तर हासिल किया, जो विभिन्न संकेतकों में मजबूत प्रदर्शन को रेखांकित करता है। बैंकों की लाभप्रदता भी मजबूत रही, जिसका प्रमाण 31 मार्च 2024 तक के उनके 13.8 प्रतिशत इक्विटी प्रतिलाभ (आरओई) और 1.3 प्रतिशत आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) से दिखाई देता है।

समग्र स्तर पर देखें तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने भी मार्च 2024 के अंत तक बेहतर प्रदर्शन किया है जिसमें उनका सीआरएआर 26.6 प्रतिशत, जीएनपीए अनुपात 4.0 प्रतिशत और आरओए 3.3 प्रतिशत रहा।

वित्तीय प्रणाली के इस मजबूत प्रदर्शन और स्वस्थ वित्तीय स्थिति के बावजूद, एक विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, हमें क्षितिज पर खड़े जोखिमों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने कुछ क्षेत्रों में अरक्षित खुदरा ऋणों में हुई मजबूत वृद्धि पर अपनी चिंता प्रकट की है। प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि ने भी

* 19 जुलाई 2024 को मुंबई में जे पी मॉर्गन इंडिया लीडरशिप सीरीज़ व्याख्यान में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया भाषण। इन टिप्पणियों को तैयार करने के लिए मनोज कुमार पोद्दार, प्रदीप कुमार, कविता गंगवाल और रूपेश कनौजिया से सामग्री प्राप्त हुई।

[1] आरबीआई बुलेटिन जून 2024, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति।

[2] 12 जुलाई 2024 को उप गवर्नर एम डी पात्र द्वारा 'भविष्य के लिए तैयार होती भारत की मौद्रिक नीति' पर दिया गया भाषण।

साइबर जोखिमों के खतरे को बढ़ा दिया है। हम अपनी निर्धारित बैठकों के दौरान इन मुद्दों पर विनियमित संस्थाओं को संवेदनशील भी बनाते रहे हैं। पारदर्शिता बढ़ाने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आचरण संबंधी मामलों पर भी हम जोर दे रहे हैं।

जलवायु जोखिम और नेतृत्व चुनौती

लेकिन अब मैं एक ऐसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ जो भविष्य में हमें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाला है। वह विषय है जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और हमारी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली पर उसका प्रभाव। ये परिवर्तन खंडीय, भौगोलिक और वैचारिक सीमाओं से परे हैं। नेतृत्व स्थान पर रहने के कारण आपको एक रणनीतिक दृष्टिकोण रखना होगा और एक दीर्घकालिक विचार अपनाना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उभरती चुनौतियों के प्रति सचेत रहते हुए टिकाऊ विकास के परिणाम प्राप्त करने के मार्ग पर आवश्यक प्रेरणा, दृढ़ विश्वास और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। जलवायु के मुद्दे से निपटने के लिए अलग-अलग क्षेत्र के नेताओं के सामूहिक दूरदर्शी नेतृत्व की आवश्यकता है क्योंकि व्यक्तिगत प्रयास कम पड़ सकते हैं या अप्रभावी साबित हो सकते हैं।

वर्तमान समय में नेतृत्व संबंधी कई चुनौतियां हैं। वास्तव में, 'पॉलीक्राइसिस' शब्द जलवायु, भू-राजनीति आदि से जुड़ी चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करने लगा है। इन सभी मुद्दों के बीच जलवायु परिवर्तन का मुद्दा सर्वव्यापी है और यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र - वित्तीय, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर नेतृत्व क्षमता को साबित करने की मांग कर सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कई समुदायों के जीवन और आजीविका को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस तरह की चुनौती के लिए हर क्षेत्र के नेताओं द्वारा आपसी सोच-विचार करके विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

इन सब के होते हुए, मैं आज जलवायु चुनौती के वित्तीय पहलुओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में वित्तीय समुदाय को क्यों प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए यहां तक अपनी टिप्पणी सीमित रखूंगा। देखने जाएं तो जलवायु परिवर्तन के जोखिम भौतिक दुनिया से संबंधित हैं, लेकिन ऐसे जोखिमों में भौतिक से वित्तीय तक तेजी से पहुंचने की क्षमता होती है, और इसी से वित्तीय क्षेत्र की भूमिका ध्यान में आती है। कई बार, जलवायु मुद्दों के संबंध में वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, विशेष रूप से केंद्रीय बैंकों की भूमिका के बारे में बहस होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर जलवायु घटनाओं का स्पष्ट असर पड़ता है। ये दो ऐसे व्यापक विषय हैं जिनके बारे में अधिकांश केंद्रीय बैंकों को बहुत अधिक ध्यान रखना होता है। जलवायु घटनाएं स्थावर क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। चूंकि इन क्षेत्रों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाता है, इसलिए इसका बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के जोखिम प्रबंधन ढांचे पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए मौद्रिक नीति के साथ-साथ विवेकपूर्ण नीति के दृष्टिकोण से, जलवायु जोखिमों से संबंधित मुद्दों पर केंद्रीय बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चूंकि जलवायु परिवर्तन में मौद्रिक स्थिरता, संवृद्धि, वित्तीय स्थिरता और विनियमित संस्थाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ता को आघात पहुंचाने की क्षमता है, इसलिए एक तरह से वह केंद्रीय बैंकों और विनियामकों की कार्रवाई को भी प्रभावित करता है।

भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो बर्फ से ढके पहाड़ों, उपजाऊ मैदानों, रेगिस्तानों और अलग-अलग तापमान और वर्षा स्तर वाली लंबी तटरेखा के साथ हमारी विविध स्थलाकृति संवृद्धि और मुद्रास्फीति संबंधी चुनौतियों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के जोखिम उत्पन्न करती है। मानसून की बारिश पर अत्यधिक निर्भर कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2023-24 की *अल नीनो* घटना इस संकट का उदाहरण है। ऐसी घटनाओं से गर्मी बढ़ती है, उत्पादकता कम होती है, मानसून अपर्याप्त रहने से जलाशयों के स्तर प्रभावित होते हैं और कृषि उत्पादन कम होता है। खाद्य मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण इन कारकों का मुद्रास्फीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कृषि पर निर्भरता एक अतिरिक्त तत्व है जिसका उनके खर्च स्वरूप पर असर पड़ता है और परिणामस्वरूप देश के विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जलवायु से संबंधित घटनाएं ऋण गुणवत्ता और उधारकर्ताओं की ऋण-चुकौती क्षमताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। वे संस्थागत वित्त से बनाई गई आस्तियों को नष्ट कर सकती हैं जिससे वित्तीय संस्थानों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।

ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जोखिम प्रबंधन के पारंपरिक तरीके, जैसे जोखिम से बचना, जोखिम कम करना, जोखिम साझा करना और जोखिम हस्तांतरण पूरी तरह से प्रभावी

नहीं हो सकते हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन से वित्तीय और अन्य जोखिम आंशिक रूप से या व्यक्तिगत आधार पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र या उद्योग में सामूहिक रूप से प्रकट और प्रभावित होते है। अकेले बीमा जैसे पारंपरिक साधन ऐसे व्यापक जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। इससे बीमाकर्ताओं को भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, हमें यह स्वीकार करना होगा कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम को किसी एक कार्य समूह द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसके लिए सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से विचार करना आवश्यक है। एक शाश्वत भविष्य की ओर सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए हमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकारें, निजी क्षेत्र की संस्थाएँ, वित्तीय संस्थान, नागरी समाज संगठन और जनता शामिल हो।

जलवायु बनाम संवृद्धि - 'न्यायसंगत संक्रमण' की अवधारणा

जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के प्रस्ताव कभी-कभी विरोधाभासी विचारों को जन्म देते हैं क्योंकि जलवायु के पक्ष में की जाने वाली कार्रवाइयों को आर्थिक विकास और रोजगार से समझौता करने वाला माना जाता है। इसके बावजूद, तत्काल और संतुलित तरीके से कदम उठाने की आवश्यकता है। हम विलंब नहीं कर सकते। बढ़ते तापमान और जलवायु घटनाओं से निपटने के लिए पहले से ही भारी वित्तीय लागत लग रही है, इसके अलावा वे पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति भी पहुँचा रहे हैं। यदि हम जल्दी शुरू करते हैं, तो अधिक शाश्वत भविष्य की ओर संक्रमण की लागत कम होगी और वह लंबे समय तक विस्तारित रहेगी।

इसलिए, मेरा मानना है कि जलवायु जोखिम को कम करने पर जल्दी काम करने से दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। जलवायु कार्रवाई में निवेश से मध्यम और दीर्घकालिक रूप से अच्छे प्रतिफल मिलेंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्पकालिक प्रभाव कुछ देशों के लिए असंगत नहीं होने चाहिए, अर्थात संक्रमण प्रक्रिया के दौरान उनकी स्थिति और खराब न हो। इसलिए, ईएमडीई को अधिक जलवायु वित्त उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा ईएमडीई को संक्रमण प्रक्रिया में मदद करने के लिए उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की जलवायु निधि संबंधी दृढ़ और स्थायी प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है।

जलवायु जोखिमों के प्रबंधन में अनुकूलन और संक्रमण प्रमुख रणनीतियाँ हैं। हालाँकि, विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्थाओं पर अनावश्यक बोझ डाले बिना संक्रमण सुगमतापूर्वक, सभी को साथ लेकर और न्यायसंगत होना चाहिए। हमें वर्तमान में उपस्थित चुनौती को भी संबोधित करने की आवश्यकता है, जो कि कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को वित्तपोषित करने के संबंध में है। ईएमडीई के अत्यधिक निधि अंतराल और अत्यधिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को देखते हुए (भारत के मामले में अनुमान जीडीपी के 2.5 प्रतिशत से लेकर ईएमडीई के लिए 2030 तक प्रति वर्ष 2 ट्रिलियन डॉलर तक है) संक्रमण वित्त तक पहुँच महत्वपूर्ण है।

ईएमडीई को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि वे न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, बल्कि उनके पास छोटे उद्यमों की प्रधानता और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के अलावा संसाधन की अधिक कमी भी है। एनजीएफएस द्वारा हाल ही में जारी किया गया प्रकाशन जिसका शीर्षक है "टेलरिंग ट्रांजिशन प्लान्स: कंसीडरेशन्स फॉर ईएमडीई" विकासशील देशों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों को सही ढंग से उजागर करता है। यद्यपि 'जस्ट ट्रांजिशन' (न्यायसंगत संक्रमण) की अवधारणा ने विभिन्न क्षेत्राधिकारों की जलवायु नीतियों में प्रमुखता प्राप्त की है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि उसे संक्रमण प्रक्रियाओं पर लागू किया जाए।

संक्रमण वित्त की आवश्यकता को देखते हुए अगला स्पष्ट प्रश्न यह उठता है कि इसके लिए योजना कैसे बनाई जाए। इसलिए विश्वसनीय संक्रमण योजनाओं की आवश्यकता है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एक साथ कई उद्देश्यों को संबोधित करने की आवश्यकता के बावजूद, ईएमडीई में संक्रमण योजना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ गैर-वित्तीय संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी जुटाने और जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए संक्रमण योजनाएँ आवश्यक हैं।

संक्रमण योजनाएँ रणनीतिक और शीर्ष-संचालित होनी चाहिए। उसमें भौगोलिक क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग और इकाई स्तरों के लिए भी स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए। इसके अलावा, संस्थाओं को विशिष्ट जोखिमों को कम करने के लिए संचालन,

उत्पादन, सेवाओं और नीतियों में विस्तृत योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है। इसी तरह, उद्योग-विशिष्ट संक्रमण योजनाओं को विनियमों का पालन करके, प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर और हितधारकों के साथ सहयोग करके क्षेत्र की जरूरतों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि संस्थाएं और उद्योग, दोनों अपनी अलग-अलग चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रभावी ढंग से योगदान देते हैं।

हालांकि संक्रमण महत्वपूर्ण है, किंतु हम जलवायु घटनाओं के तत्काल प्रभावों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए, अनुकूलन की ओर भी देखने की आवश्यकता है जो जलवायु रणनीतियों के विकास के मामले में ध्यान में न आई हुई एक कड़ी है। अनुकूलन में जलवायु घटना के प्रभाव से निपटना शामिल है। ये घटनाएं दैनिक जीवन के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्थितियों, जैसे कि पानी, ऊर्जा, वायु गुणवत्ता और सहनीय कार्य तापमान तक पहुंच को लगातार नुकसान पहुंचाती हैं। ये स्थितियां तूफान, बाढ़ और जंगल की आग जैसे अल्पकालिक आघातों से बाधित हो सकती हैं, जिनके प्रभाव अचानक और विनाशकारी होते हैं। नुकसान और क्षति को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और आपदा तैयारी योजनाओं की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है और इसलिए अनुकूलन वित्तपोषण आर्थिक सुदृढ़ीकरण और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने का एक तरीका अनुकूलन वित्तपोषण को सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रबंधन ढांचे में एकीकृत करना है।

इन स्थितियों में विनियामकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे न केवल वित्तीय क्षेत्र के लिए विनियम निर्धारित करते हैं बल्कि भविष्य की कार्यवाहियों के लिए स्थावर क्षेत्र को संकेत भी भेजते हैं, जिससे कि उन्हें अपनी भविष्य की रणनीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण दिशा मिल सके। साथ ही, निजी स्रोतों द्वारा वित्त पोषण में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, विनियामकों को जलवायु वित्त के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सही जलवायु सूचना व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप प्रकटीकरण ढांचे की भूमिका महत्वपूर्ण है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि विकास और जलवायु-संरक्षण के उद्देश्यों को इष्टतम तरीके से जोड़ना संभव है। एक बार जब हम सक्षम ढांचे स्थापित कर लेते हैं तो व्यवहार्य परियोजनाओं की एक व्यवस्था बनाने तथा अभिनव जलवायु वित्तपोषण उपायों के रूप में अनुकूलन वित्त[3], मिश्रित वित्त[4] जैसे नए वित्तीय साधनों को विकसित करने में अर्थव्यवस्था सक्षम होगी। इस प्रकार की आधारभूत व्यवस्था बन जाने पर विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करने के लिए संभावित नीति दिशा बिंदुओं में (i) प्रकटीकरण आवश्यकता (ii) जोखिम प्रबंधन (iii) ग्रीन क्रेडेंशियल्स के तीसरे पक्ष के सत्यापन का मजबूत नेटवर्क और ग्रीन वॉशिंग चिंताओं को दूर करने के लिए परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन और (iv) आवधिक दबाव परीक्षण को जोखिम शमन उपायों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

एक देश के रूप में भारत ने भी जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हमने 2015 में यूएनएफसीसीसी को अपने 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (एनडीसी) प्रस्तुत कर दिए हैं, और 2021 में सीओपी26 में उसका अद्यतन पाठ भी प्रस्तुत कर दिया है। भारत ने "पंचामृत" के रूप में जानी जाने वाली अपनी व्यापक रणनीति के माध्यम से महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाना, नवीकरणीय स्रोतों से 50% ऊर्जा प्राप्त करना और 2030 तक जीडीपी कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना है। सीओपी27 में दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीतियों (एलटी-एलईडीएस) की शुरुआत, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सह-स्थापना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत, मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कदम हैं।

रिज़र्व बैंक ने भी प्राथमिकता क्षेत्र ऋणों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, हरित जमा शुरू करने और जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों के लिए प्रकटीकरण रूपरेखा का मसौदा तैयार करने जैसे सक्रिय कदम उठाए हैं। निकट भविष्य में हम बीसीबीएस सिद्धांतों के आधार पर परिदृश्य विश्लेषण, दबाव परीक्षण और जलवायु-संबंधी वित्तीय जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन पर मार्गदर्शन जारी करने की योजना बना रहे हैं।

---

[3] अनुकूलन वित्त सुदृढ़ीकरण और आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

[4] नया साधन जो लोक हित और निजी पूंजी को जोड़ने में मदद कर सकता है।

आरबीआई@100[5] के लिए आरबीआई के आकांक्षात्मक लक्ष्यों में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए एक मजबूत विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचा स्थापित करना, जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए भुगतान प्रणालियों की सुदृढ़ता बढ़ाना और एक व्यापक वर्गीकरण को अंतिम रूप देने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना शामिल है।

निष्कर्ष

भारत ने 2024 में जी20 सदस्यों के बीच जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सीसीपीआई)[6] का उच्चतम स्थान हासिल किया है, जो इस उद्देश्य के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे यह भी दिखाई देता है कि आर्थिक नीतियों को जलवायु कार्रवाई के साथ जोड़कर हम हरित निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, ऊर्जा दक्षता बढ़ा सकते हैं और सभी क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। वैश्विक स्तर पर "न्यायसंगत संक्रमण" (जस्ट ट्रांजिशन) की अवधारणा को अपनाकर, हम एक शाश्वत भविष्य की ओर एक मार्ग तैयार कर सकते हैं जो सभी के लिए समृद्धि सुनिश्चित करता हो और साथ ही हमारे ग्रह को भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता हो। संपूर्ण विश्व को एक परिवार और पृथ्वी को उसका एकमात्र आवास मानते हुए, एक स्थायी तरीके से आर्थिक विकास किया जाना जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का एक साथ समाधान कर सकता है। यहाँ, ऋग्वेद की उन श्रेष्ठ पंक्तियों को उद्धृत करना उचित होगा, जिसे हमने अपने जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान प्रचारित किया था:

"अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्॥"

"यह मेरा है, वह तुम्हारा है –
यह संकीर्ण हृदय वाले लोगों के मन की गणना है।
तथापि, उदार लोगों के लिए,
संपूर्ण विश्व एक परिवार है।"

ऐसा माना जाता है कि आप स्वयं अपने भविष्य के निर्माता होते हैं। अपने-अपने संगठनों में नेतृत्व स्थान पर होने के नाते आइए हम प्रत्येक निर्णय को महत्वपूर्ण बनाएं क्योंकि यह एक साझा और समृद्ध भविष्य की ओर एक कदम है। आज के हमारे प्रयास कल की वास्तविकता को आकार देंगे। मैं कामना करता हूं कि इस कार्यक्रम के दौरान विचार-विमर्श और चर्चाओं के परिणामस्वरूप जलवायु संवेदनशील विकास के साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नवीन विचार सामने आएं।

धन्यवाद। नमस्कार!!

---

5 https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=58049

6 https://ccpi.org/